माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, द्वारा दिनांक–27.07.2015 को रिपोर्ट कार्ड, का लोकार्पण कार्यक्रम में दिये गये भाषण का ट्रांसक्रिप्शन

हमारे मंत्रिमंडल के सभी यहॉ उपस्थित सहयोगीगण, बिहार सरकार के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक, हमारे बीच उपस्थित बिहार के माननीय विद्वान अधिवक्ता, सभी अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहॉ उपस्थित प्रतिनिधिगण, छायाकार बन्धु।

आज आपके बीच 10 साल के कार्यो पर आधारित रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए मैं सबसे पहले आपलोगों का स्वागत करता हूॅ। मैने इस परम्परा की शुरूआत की। 2005 में पहली बार लोगों ने काम करने का मौका दिया। पहले विधान मंडल में इस बात की घोषणा की कि हम हर वर्ष अपने सरकार के काम का लेखा–जोखा एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में प्रस्तुत करेंगे और तब से ये परम्परा की शुरूआत हुई और इसे अनवरत हमने जारी रखा और आज हम 10 वॉ साल में है। बिहार के लोगों ने 2010 में पुनः काम करने का मौका दिया तो इस बार कोई 10 वॉ साल का अबतक का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि पूरे 10 साल में पूरा किया गया काम का लेखा–जोखा देना मुनासिब समझा और इसी दृष्टिकोण से आपके सामने आपके माध्यम से बिहार के जनता के सामने हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। जब लोगो ने काम करने का मौका दिया तो हम ने 2005 से 2010 के बीच और दुबारा काम करने का मौका दिया तो 2010–2015 के लिए एजेंडा पर सदन में सुशासन के कार्यक्रम हमने तय किए। उस कार्यक्रम को लागु करने में हम कामयाब रहे और यहॉ तक की सुशासन के कार्यक्रम में जो कार्यक्रमों का उल्लेख है उसे भी आगे बढ कर हमने योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं को क्रियान्वित किया। राज्य के उपर जो जवाबदेही होती है उस जवाबदेही का पूरी निष्ठा के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ, निर्वह्ण किया। राज्य की पहली जिम्मेवारी होती है शान्ति व्यवस्था बहाल करना और हमने 2005 में सरकार बनाने से पहले लोगो के लिए वादा किया था कि बिहार में हम कानून का राज्य कायम करेंगे। और न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। यही हमारी मार्गदशक सिद्वांत और हमने बिहार में कानून का राज्य कायम किया। कानून अपना काम करता हैं। चाहे वह विधि व्यवस्था का संधारण हो या आमलोगों के मन में सुरक्षा का एहसास हो। उस क्षेत्र में काम हुआ। लोगों का विश्वास पैदा हुआ। लोगों के मन में सुरक्षा का ऐहसास हुआ, लोगों के मन से डर निकला और आज कोई भी व्यक्ति आपने घर से निकालकर व्यक्तिगत या सामाजिक कार्य के लिए जब जरूरत पड़ता है तो आपने घर से निकालकर गंतव्य की ओर जाता है। और उसके मन में झिझक और संकोच नहीं होता है। बाहर में बिहार के बारे में छवि बनी है। बाहर के लोग बिहार आने से डरते थे। अब बाहर के लोग बिहार आने के लिए इच्छुक रहते हैं। अब जो लोग बिहार आते है वह पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते है कि बिहार बदल गया। यह आम धारणा थी पूरे देश में कि बिहार बदल ही नही सकता। बिहार आगे बढ ही नहीं सकता । हमने इस धारणा को बदल दिया और आज बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हर क्षेत्र में विकास हुआ हैं। जैसा हमने पूर्व में कहा हमने न्याय के साथ विकास के मार्ग का अवलबंन किया। समाज के हर तबके को विकास का लाभ मिले और विकास के कार्य में हर तबके

की भागीदारी को हमने सुनिश्चित किया। बिहार पहला राज्य था जिसने महिलाओं को पंचायती राज्य संस्थाएँ में, नगर निकायों में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया। संविधान में व्यवस्था है कि कम–से कम एक तिहाई स्थान महिलाएँ के लिए आरक्षित रहेगी हमने भी सोचा कम–से–कम 33 प्रतिशत हो। आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और फिर इसे हमने सुनिश्चित किया। उसके बाद शिक्षिकाओं के नियुक्ति के लिए हमने 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया और बात वहॉ से आगे बढी और जब हम उन्हें 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो उनकी शिक्षा पर भी जोऱ देंगे। हमने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। सबकी शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया चाहे वो महिलाएँ की साक्षरता प्रश्न हो। अक्षर ऑचल योजना के जरिये हमने साक्षरता के दर में वृद्वि लाई। साक्षरता के मामले में बिहार बहुत पिछडा हुआ था। चाहे पुरूष के बीच साक्षरता हो या महिलाएँ के बीच साक्षरता हो लेकिन हमारे कदम इस तरह से आगे बढे कि 2005 से 2010 के बीच में जो साक्षरता में वृद्वि हुई है जो देश में महिलाओ के साक्षरता दर में एक दशक के अन्दर में जो प्राप्त हुआ वह बिहार का सर्वाधिक रहा और इसके चलते बिहार को पुरस्कृत किया गया। लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयोग किए गए। पोशाक योजना, इनके सहारे लड़कियों की संख्या स्कूलों में बढी और लडकियों के लिए साईकिल योजना की शुरूआत की तो उसमें तो एक तरह से सामाजिक परिवर्तन ला दिया। पटना शहर में भी लड़कियाँ साईकिल चलाती नहीं थी लेकिन लडकियॉ गॉव–गॉव में साईकिल चला कर स्कूल जाने लगी। लोगों की मानसिकता और नजरिया में बदलाव आने लगा एक लाख सत्तर हजार लड़कियॉ थी जब हमलोगों ने पहली बार साईकिल योजना शुरूआत की और आज नौवे क्लास में पहुचने वाली लडकियों की संख्या आठ लाख से भी ज्यादा हो गया।यह अपने आप में एक रिकार्ड है। लड़कियों के साईकिल योजना के बाद लड़कों के लिए भी साईकिल योजना की शुरूआत की, और नतीजा है कि देश के बाहर के लोग भी बिहार की इस योजना का अध्ययन करते हैं। कई अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों ने इस का अध्ययन किया और इसको सफल माना। यहॉ तक कि दुनिया के जिन इलाकों में शैक्षणिक पिछडापन है वहॉ के लिए सुक्षाव दिया कि इस योजना को अपनाना चाहिए। बिहार में विकास का मतलब लोगों का विकास। हमने लोगों का विकास पर ध्यान दिया और उसके साथ–साथ कानून का राज्य कायम करते हुए लोगों के विकास पर ध्यान देते हुए हमने बुनियादी ढॉचे के विकास के लिए भी काम किया। बडे पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ। बिजली की स्थिति में सुधार लाने का प्रत्यन की जा रही है। और बेशक सुधार आये है।जो प्रगति हुई है उसे सब लोग महसूस कर रहे है। लोगों के मन में ऐहसास है। 12 प्रतिशत से भी ज्यादा लडके स्कूलों के बाहर रह जाते थे। आज वह संख्या 1–2 प्रतिशत के बीच रह गई है। ड्रॉप आउट घट गया। नये स्कूलों की स्थापना हुई अब तो नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रत्येक पंचायत में स्थापित हुई स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ चरमराई हुई थी लोग चिकित्सा के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर थे। वही से हमने शुरूआत की। यह लिखित आंकडा है। जब 2006 में फरवरी महीने में सर्वेक्षण कराया तो पता चला औसतन एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 39 मरीज जाते थे। वहॉ से हमलोगों ने शुरूआत किया। डॉक्टर और पारामेडिकल स्टॉफ की उपस्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुनिश्चित कराएँ, मुफ्त दवा के वितरण की शुरूआत की और नतीजा हुआ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डेली जाने वाले मरीजों की संख्या

बढ़ने लगी और आज आंकडे बताते है कि अब औसतन एक महीना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 11 हजार मरीज जा रहे है अपना ईलाज कराने। 39 से शुरूआत हुई और अब 11 हजार मरीज। इसमें और अनेक प्रकार के सुधार लाई गई और अब तो द्वितीय चरण के सुधार पर काम चल रहा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सामने चुनौती थी। और अब शिक्षा के गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया हैं तो हर क्षेत्र में अब द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं । उस क्षेत्र में प्रगति हो रही है, और आगे भी प्रगति होती रहेगी। सड़क के क्षेत्र में जो आंकडा है वो बतलाते है कि कितना काम हुआ। कुल मिलाकर 2005 से लेकर अब तक पथ निर्माण विभाग, ग्रमीण कार्य विभाग, दोनो मिलकर 66 हजार पॉच सौ किलोमीटर से अधिक वृहत और ग्रमीण सडकों का निर्माण और अन्य कार्य किया। 10 वर्षो में ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। छियासठ हजार पॉच सौ किलोमीटर सड़को का निर्माण। यहॉ हमारी पुरानी सडकों की योजना होगी। पॉच हजार चार सौ से भी ज्यादा पुलों का निर्माण हुआ। इसके अलावे सड़कों पर पुलों का निर्माण किया गया बडे पुलों का निर्माण हुआ। महासेतु का भी निर्माण हुआ। आप सब जानते हैं चाहे गंडक हो, कोशी, गंगा, बुढी गंडक सोन नदी पर हो और हम पथ के मेंटेनस के पोलिसी को अपना चुके हैं, वह अपने आप उसका **Maintenance** हो रहा है। बिजली के बारे कई तरह के भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है। बिजली के क्षेत्र में हमलोगों ने काम किया और 2012 में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को गॉधी मैदान पटना में झंडोतोलन के बाद अपने बात को कह दिया कि बिजली की क्षेत्र में सुधार लायेगें और सुधार नहीं लायेंगे तो लोगों के बीच 2015 में वोट नहीं मांगने जाएगें और हमने उस संकल्प पर तेजी से काम किया और आज उपलब्धियाँ भी हासिल हुई। यहॉ 2005 में बिहार में बिजली का **Per Capita Consumption** 70 यूनिट था। वह बढ कर 203 यूनिट हो गया। उस समय बिजली की आपूर्ति मात्र 700 मेगावाट थी। अब बढकर 3012 मेगावाट हो गई । हमलोंगों के अथक प्रयास से छत्तीस हजार से ज्यादा गॉव का विद्युतीकरण हो चुका है। इसमें से 26373 गॉव में पूर्णरूप से विद्युतीकरण हो गई हैं। 9759 गॉव में आंशिक विद्युतीकरण हुआ। विद्युत फीडर की संख्या 45 से बढकर 97 हो गई। ट्रांसमिशन लाईन की लम्बाई 5000 सर्किट किलोंमीटर से बढकर 8638 सर्किट किलोमीटर हो गई। किन किन बातों का उल्लेख करें। पावर डिस्ट्रिब्यूटशन के लिए जो पावर कहते हैं उसकी क्षमता विस्तार 1000 मेगावाट थी आज वह बढकर 4400 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। तो निरंतर ट्रासफॉर्मर के बदलने की सिलसिला हो 23146 ट्रासफॉर्मर जले और खराब थे। जिसमें 18510 ट्रासफॉर्मर को बदला जा चुका और शेष में बदलने की कार्रवाई चल रही है। बिजली की उपलब्धता बहुत कम थी और अब शहरी क्षेत्र में 22–24 घंटे एवं ग्रमीण क्षेत्र में 15–16 घंटे हम बिजली की आपूर्ति की। तो बिजली की स्थिति में सुधार आई है। सडकों की स्थिति पुलों की स्थिति और अब सब को मालूम है कि हमने एक लक्ष्य घोषित किया था कि बिहार के सुदूर ईलाके से चलकर पटना पहुॅचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नही लगना चाहिए और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस लक्ष्य को निर्धारित किया गया उस लक्ष्य को अब 6 घंटे नही अधिक से अधिक 5 घंटे लगना चाहिए इस पर लोगों ने काम किया। इस हिसाब से जरूरत के मुताविक सडकों का निर्माण पुलों का निर्माण किया। 250 की आबादी तक गॉव को पक्की सडक से जुडने की योजना पर अमल हुआ तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में काम हुआ। प्रशासनिक सुधार किये गए। कानून का राज्य कायम किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया गया और हमलोगों ने भ्रष्टाचार के

खिलाफ **Zero Tolerance** की नीति लाई। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाशत नहीं की जायेगी। सम्पति जब्त करने का प्रावधान किया कई लोगों की सम्पति जब्त की गई और उसमें स्कूल खोल दिया गया। उसके अलावे जो सरकारी सेवा में लगे है उनके विरूद्व अपराधिक और प्रशाासनिक दोनों प्रकार की कार्रवाई की गई। 1032 मामलें मे जो घूस लेते रंगे हाथ पकडे गए थे, **Improportionate** धन का अर्जन या पद का दुरूपयोग संबंधी संलिताओं में 1032 मामलों में 763 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। विभागीय कार्रवाई संचालित कर 487 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया, पेंशन जब्त किया गया। 119 कर्मी को अन्य प्रकार के दंड दिए गये तो ये हमलोगों का काम चलाता रहा है। हमने जनता के सुविधा के लिए **Call Centre** बनाया। **Right to Information Act** सूचना का अधिकार कानून उसमें बिहार में हमलोगों ने प्रयोग किया। जानकारी **Call Centre** के जरिये भी आप सूचना प्राप्त करने का आवेदन दे सकते है। आवेदन देने के विकल्प के रूप में हमलोगों ने इसे शुरूआत किया। इसके अलावे हमने सरकार में न्याय के लिए लोक सेवा अधिकार कानून बनाए **Right to Public Service Act** जो सेवाएँ सरकार प्रदान करती हैं वह सेवा पाने का जनता का कानूनी अधिकार है, और यह अधिकार है, और यह अधिकार हमलोगों ने प्रदान किया है। चाहे वे किसी तरह का सर्टिफिकेट लेते है चाहे आमदनी का हो, जात का हो, डोमीसाईल हो या अन्य प्रकार की, सर्टिफ्किेट हो, और कई प्रकार की सर्टिफिकेट हो, और वे कई प्रकार की सर्टिफिकेट प्राप्त करते है कानून के जरिये और इसे लागू किया।

आज मुझे ये सूचना देते हुए प्रसंन्ना हो रही हैं कि 10 करोड से भी ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस प्रकार की सेवाएँ 9 विभागों के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें कुल 102172716 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 101452910 आवेदनों का निस्तार किया गया। उपलिब्ध है 99.3 प्रतिशत। ये लोक सेवा कानून बनाया। इस तरह से ये काम किया गया। प्रशासनिक सुधार किये गए और एक चीज और था इसकी जानकारी देने वाला हूँ इसकी जानकारी वो मै आखरी में आउॅगा। इस से आगे बढकर अब जो लोगो की शिकायते है उनके निवारण का भी हम प्रबंध करेंगे। एक लम्बे काल से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और जनता दरबार में अन्य अधिकारी के कार्यक्रम की शुरूआत कराई गई। उसके अच्छे परिणाम आये लेकिन अब हमलोगों ने सोचा है कि लोक शिकायत के निवारण के लिए भी कुछ ऐसा व्यवस्था की जाए कि लोगों को इसका अधिकार मिले तो उसके बारे में निर्णय लेने के बाद में चन्द मिनटों के बाद जानकारी दें देगे। हर क्षेत्र में चाहे कानून का राज्य स्थापित करना है भ्रष्टाचार के रोक पर कार्रवाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो इन सब चीजों पर और ये सब काम करते हुए बिहार में प्रगति हुई है। दुनिया ने इस प्रगति को देखा है। दुनिया ने उस पर अध्ययन किया और लोगों ने सराहा है। अब हमारा ग्रोथ जो विकास दर रहा है, वर्तमान मूल्य पर वह 17 प्रतिशत से ज्यादा हो चुका है। जो हमारा राज्य के सकल उत्पाद था 2004–2005 में 7778 करोड। हमारा पूरे बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2004–2005 मे और आज 2014–2015 में यह बढकर 402282 करोड हो गया है यानी 77 हजार करोड से बढकर 4 लाख करोड से भी ज्यादा हो गया है।

हमारा ग्रोथ **Industrial Produce** हो चुका हैं। वर्तमान मूल्य की नहीं हम स्थिर मूल्य की बात कर रहे है। वार्षिक औसत वृद्वि, वर्तमान मूल्य पर 70.99 प्रतिशत मतलब वर्तमान मूल्य पर हमारा ग्रेथ रेट 80.0 प्रतिशत है। राज्य में जो अपना कर राजस्व 3347 करोड था आज हो गया 20750 करोड रूपया। वार्षिक औसत वृद्वि 20.36 प्रतिशत है। योजना का व्यय

4000 करोड से भी कम था अब बढकर 43931 करोड यानि 10 वर्षों में 10 गुना से भी ज्यादा। हमारी योजना आकार व्यय में वृद्वि हुई है। तो ये है विकास की कहानी। बजट कितना का होता था। जब हमलोग आये थे तो उस समय का वार्षिक योजना गैर योजना 26328 करोड रूपये और अब हमारा सालाना बजट हो गया है 1 लाख 20 हजार 6 सौ 85 करोड, रूपया। 26 हजार करोड़ से बजट का आकार बढकर 1 लाख 20 हजार करोड से भी ज्यादा हो चुका तो विकास इसको नही कहते है तो किसको कहते है। बहुत लोगों को विकास नजर नही आता है तो उनकी सहायता मै नहीं कर सकता हूँ। मैने अपने ऑखों का ईलाज करवाया है। आई स्पेलिस्ट का नाम बता दे सकता हूँ जॉच करवाना है तो करवा ले। दरअसल बिहार की विकास की तस्वीर है ये और वार्षिक वृद्वि दर हो सकल घरेलू उत्पाद योजना का व्यय हो ये सब आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे है। उसके अलावे अगर आप देखेगे तो इस स्थिर मूल्य पर आये हमने तो बताया 2005–2006 से लेकर 2014–2015 स्थिर मूल्य हैं राज्य का औसतन वार्षिक वृद्वि पर 80 प्रतिशत लेकिन स्थिर मूल्य पर 10 प्रतिशत पर चल रहा हैं। 4.9 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का। कहते है कि कुछ बना ही नही। लोग कहते है कि एक सूई के भी कारखाना नही लगा यानि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का ग्रेथ 7.8 प्रतिशत। मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण और उद्योग का ग्रेथ क्षेत्र हैं ग्रोथ रेट है 13.3 प्रतिशत। परिवहन भंडारण 40.7 प्रतिशत सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का 11.4। ये सभी प्रक्षेत्रों का योगदान है, हमारे कुल ग्रोथ में और 10 साल में एभरेज ग्रोथ डब्ल डिजीट, 10 प्रतिशत हमारा रहा है। फिक्स प्राईस पर, स्थिर मूल्य पर और लगभग 80 प्रतिशत 7.99 करेंट प्रतिशत रहा है। यह बिहार की विकास की कहानी और सभी क्षेत्र का विकास हुआ। हर क्षेत्र में प्रगति हुई और इसका लाभ समाज के हर तबके को मिला हैं। हमने अनुसूचित जाति जन जाति, महादलित, अति पिछडे वर्ग पिछडे वर्ग या अन्य सवर्ण समाज के लिए भी काम किया। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया। सभी समुदाय के लिए हमलोगों ने काम किया और अभी हमलोग बात कर रहे है। रिर्पोट कार्ड पेश कर रहे है। शिविर लगाकर लगभग 3 करोड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अति पिछडे वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर पिछडे वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र–छात्रोंओं को यानि1.5 लाख रूपया के सालाना आमदनी से कम वाले छात्र–छात्राओं को छात्रवृति राशि, साईकिल योजना, पोशाक योजना, प्रोत्साहन योजना, के अंतर्गत 4 हजार करोड रूपया का वितरण हो रहा है उसके अलावे सभी प्रकार के पेंशन योजनाएँ चलाए जाते हैं। जितने प्रकार के पेंशन योजना हमलोग चलाते हैं। उसका 1 हजार करोड की राशि आवंटन हो रहा है। ये सारे लोगों को वितरित किया जा रहा हैं। ये लोगों का हर हाल में पैसा मिल रहा हैं। साईकिल का, पोशाक के लिए छात्रवृति की राशि, प्रोत्साहन की राशि, पेंशन की राशि सब काम हो रहा है। इसके आलावे भी लड़कियो के लिए हमने कहा था बिहार दिवस के अवसर पर तुमको सेफ्टी नेपकिन का भी पैसा देंगे। सेफ्टी नेपकिन का तो हमारा ध्यान खाद्य की सुरक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एक–एक चीज पर। इसके पहले भी बताया था कि लडकियों की संख्या के बारे में बहुत सुखद समाचार है और मै समझता हूँ कि जो नर–नारी समता की वकालत करते हैं उनके लिए तो और सकून देने वाली खबर हैं कि अब माध्यमिक स्कूलों में लड़कों और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई तब जबकि हमारी ये सेक्स रेशियों **Unequall** है। 1000 लड़को पर 917 लडकियाँ है। इस स्थिति में जब नर और नारी की रेशियों /लिंगानुपात असंतुलित हैं

तब भी कुल आबादी में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तब भी एक प्रयास है इसको साबित करने के लिए नौवीं कक्षा में लडकों –लडकियों की एक उदाहरण जो इस बार करंट ईयर 8 लाख 28 हजार 347 और लडकियों की संख्या हैं 8 लाख 15 हजार 8 सौ 37 लगभग बराबर, मात्र 12 हजार की फर्क रह गई है। अगर किसी एक से आज के अवसर पर प्रसन्नता है तो इस बात की प्रसन्न्ता है कि जब शुरूआत की 1 लाख 70 हजार लड़कियाँ थी नौवी क्लास की और आज 8 लाख 15 हजार से भी ज्यादा संख्या हैं। मै समझता हूँ कि मेरी दृष्टिकोण से ये सबसे बडी उपलब्धि है और विकास के मार्ग ये प्रस्तुत करेंगी बिहार का। विकास को यह अपना नजरिया है। बोलचाल की भाषा में समझें तो विकास का बिहार का यह मॉडल हैं जब लडके और लडकिया की संख्या क्लास नौवी में बराबर हो गई। और मैं बार–बार कहता हूँ कि बिहार का विकास का अपना–अपना नजरिया है। यही है बिहार का मॉडल **Human Development Indicator**। हम यदि सारे **Indicator** का जिक्र करें तो समय लगेगा। हमलोगों ने रिपोर्ट कार्ड के अलावे उसका **summary** भी बना दिया है। उसे पढ ली जाय। संक्षेप बिन्दुओं में ये सारे आंकडे आपके समक्ष रखे गए है। **Human Development** को एक नजर देख ली जाये तो टिकाकरण, पोलियों का तो उन्मूलन हो चुका है। दुनिया भर में बिहार भर में पोलियों का उन्मुलन हो गया। पिछले तीन वर्ष में पोलियों का एक भी केस नहीं है। हमने टीकाकरण पर भी ध्यान दिया। 18.6 प्रतिशत और अब हमारे यहॉ टीकाकरण का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बढकर 78 प्रतिशत हो गया। यह विकास का रास्ता। हमारे बच्चे बीमारी से ग्रस्त नहीं होगें तभी वह आगे बढ पायेगे उनकी पूरी क्षमता का उपयोग होगा। हमने सब पर ध्यान दिया। **Rule and Law Human development** कानून का राज, बुनियादी ढॉचे का विकास और मानव का विकास समाजिक रूप से विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कितने इससे संबंधित संरचना दिया। नये–नये संस्थान बने यह बिहार सरकार की पहल है। लोगों की पहल हैं कि बिहार में आई0आई टी0 पटना आया। हमारे पूर्व की पहल थी एन0आई0टी0 पटना बना। चन्द्रगुप्त,आर्यभटट विश्वविद्यालय, नेट, नेशनल स्कूल, फैशन टेक्नोलॉजी उसमें सारा पैसा राज्य सरकार लगाती है। हर चीज, स्थापना का व्यय, स्ट्रक्चर जो राज्य वहन करती है। उनके लोग पढाते हैं, चलाते हैं उसका खर्च राज्य वहन करती है। लेकिन जो भी खर्च होता है राज्य सरकार देती है। केवल बैनर रहता है एन0आई0टी0 का। बहुत लोगों को भरम होता है। यही शर्ते होती है एन0आई0टी0 का। हमलोग शर्तो को मान कर एन0आई0टी0 की शुरूआत की। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बिहार में एक नया कृषि विश्वविद्यालय जब राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात चली तो हमने अनुरोध किया। हमलोगों ने कानून बनाकर अपना काम कर लिया पॉच साल पहले और अपना एक और विश्वविद्यालय स्थापित किया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बिहार कृषि विश्व विद्यालय में पॉच नये कॉलेज भी स्थापित किया गया। डुमरॉव में बीरकुँवर सिंह, कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया। पढाई पहले से चल रही है नुरसराय हस्तकरघा कॉलेज इसका भी उद्घाटन हो गया। किशनगंज कृषि महाविद्यालय का उद्घाटन करने हम जा रहे है। पूर्णिया और किशनगंज में विद्यालय स्थापित किया। अभी तो लोग योजनाएँ ही बना रहे हैं। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सेंन्ट्रल **university** बनायेगी पहली बार उनलोगों ने बताया की कितने पैसा कृषि विश्वविद्यालय में व्यय हुआ। ये प्रपोजल सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी की है कि हमारे यहाँ राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय बनायेंगे। सारी संरचना के साथ लाया। सारी **Liability** ले रहे।

पुरानी जितनी भी **Liability** है जो हमलोग ले रहे हैं। तो वह कोई गलत प्रश्न थी। मेडिकल कॉलेज की स्थापना,इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना, डेन्टल कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया। आई टी0आई0, नये–नये अनेक **Institute** बनाए। तो विकास की ये कहानी है, दास्तॉ है और सब लोग हैं कृषि के क्षेत्र में, 76 प्रतिशत लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। तो हम कृषि के विकास पर रोडमैप बनाया पहले 2008–12। नतीजा हुआ कि हमारी उत्पादकता बढ गया हमारे किसानों ने दुनिया में धान की उत्पादकता के रिर्काड को तोडा। गेहूॅ की राष्ट्रीय मानक स्थापित किया। इन सब उपलब्धियों के साथ 2012–2017 के लिए नये रोडमैप के रिकार्ड तोडा। हमारे कृषि के केन्द्र में किसान है। उसकी आमदनी बढेगी हमारा कन्सेप्ट है कृषि के क्षेत्र में क्रांति सतरंगी क्रांति। हम चार ही रंग पर **satisfy** नहीं होने वाले हैं। हमारा तो पहले से ही सात रंग की क्रांति हो रही है। इन्द्रधनुष क्रांति अनाज, दलहन, तेलहन, फलहन, सब्जी, ईख, मशरूम, चुक्दर, मांस, अंडा, सब का उत्पादन हो। अगर सुनने की ईच्छा हो तो बता सकता हूॅ। हरा रंग सात रंगों में हरा **Greeen Revolution** खाद्य को सूचित करता है।

———————————————————